the invitation of the India-CIS Chamber of Commerce and Industry.

(b) The Government has been encouraging exchange of trade delegations, *inter alia* with the Russian Far East, in order to stimulate direct contacts between business entities in both countries. The visit of the delegation from Primorya was the first such visit from the region and served to open up a new area for trade for Indian businessmen. The Government has been encouraging visits by Indian businessmen to the Russian Far East to strengthen trade relations with the region.

Import of milk powder

1837- SHRI AJIT P. K. JOGI :
SHRI RAM GOPAL YADAV :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk powder is imported to overcome the shortage of milk in the country;

(b) if so, the names of the countries from where the milk powder is imported; and

(c) the quantity procured during the last two years?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) The milk powder is imported from countries like German Federal Republic, Ireland, Netherland, Denmark, Switzerland; Canada; France; Singapore; Belgium, UK; Malaysia; Australia; Newzealand and USA.

(c) The quantity of milk powder imported during the years 1992-93 and 1993-94 is as under:—

Year	Quantity Metric Tonne
1992-93	11994
1993-94	3000

Price rise of exportable commodities due to inflation

1838. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of COMMERCE be pleaed to state :

(a) whether it is a fact that the prices of exportable commodities have increased due to inflation.

(b) whether it is also a fact that high rate of excise duty is incompetative for exportable commodities;

(c) whether Government propose to introduce International Price Reimbursement Scheme; and

(d) if so, what are the reasons for decline in exports ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Inflation by definition, is an increase in the general price level, including the price level, of commodities meant for exports. However, its effect varies from commodity to commodity.

(b) Excise duty should not affect the price of goods to be exported as goods can be exported under bond without payment of excise duty. Goods can be exported on payment of duty and such duty can be claimed back as rebate. Besides, excise rules also provide for refunding excise duty paid on inputs used in the manufacture of export products. Under the Modvat Scheme also, credit of excise duty paid on the inputs is allowed on export of the finished products.

(c) International Price Reimbursement Scheme (IPRS) which envisaged providing Iron and Steel at International prices to the exporters of engineering goods, has been withdrawn with effect from 1-4-94. However, facility of duty free import of inputs is available under the Advance Licensing Scheme to the engineering goods exporters.

(d) There has been no decline in exports. As per the latest available data, exports during April—June 94 were valued at US $ 5613.6 million compared to US $ dollars 5127.1 million during the corresponding period of previous year.

कृषि उत्पादों के विपणन हेतु निर्यात बाजार का सर्वेक्षण

1839. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादों, विशेष रूप से ऐसे कृषि-उत्पादों के विपणन के लिए जो पारिस्थितिकी के अनुकूल हैं, निर्यात बाजार का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार पारिस्थितिकी-अनुकूल चाय की तरह पारिस्थितिकी-अनुकूल कृषि-उत्पादों के उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने व्यापार और उद्योग के सामान्य लाभ के लिए अनुसंधान संस्थानों के जरिए संगत अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए एक योजना बनायी है जिससे कि पारिस्थितिकी के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।

राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशी चीनी-व्यापारियों की निम्न विक्रय-दर को अस्वीकृत किया जाना

1840. **श्री सोमपाल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 26 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी व्यापारियों ने राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सस्ती दरों पर चीनी बेचने के लिए प्रस्ताव भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो दरों और बिक्री के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित चीनी की मात्रा सहित ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के इन प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के विस्तृत कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सर्वाधिक प्रतियोगी प्रस्ताव प्राप्त करने और साथ ही साथ आपूर्ति की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एस टी सी/एम एम टी सी ने रिफाइन्ड सुगर एसोसिएशन (आर एस ए) लंदन के सदस्य और गैर सदस्य दोनों से चीनी की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव इस शर्त पर विचारार्थ प्राप्त किए थे कि उन्हें कुछ निश्चित अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी/स्वीकार करनी होंगी। गैर-आर एस ए की उन पार्टियों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए जिन्होंने निर्धारित शर्तें मान ली जबकि पार्टियों के प्रस्तावों क अस्वीकार कर दिया गया जिन्होंने निर्धारि शर्तों को पालन करने से मना क दिया।